सार्वजनकि क्षेत्र की कंपनयिों की रणनीतकि बक्रिरी

चर्चा में क्यों?

नीतआियोग ने कुछ राज्य अधकि़ृत बीमार कंपनयिों की रणनीतकि बक्रिरी के लयि पहले सफिारशि की थी। उस सफिारशि पर मुहर लगाते हुए कैबनिेट ने कुछ सार्वजनकि क्षेत्र की कंपनयिों की रणनीतकि बक्रिरी के लयि स्वीकृतदि दी। इसके पहले वनिविेश वभिाग का नामकरण ‘नविेश और लोक परसिंपत्त प्रिबंधन वभिाग’ के रूप में दोबारा कयिा गया, जसिमें परसिंपत्त कि गुणवत्ता व सार्वजनकि क्षेत्र की कंपनयिों के कौशल में सुधार करने का स्पष्ट उद्देश्य नहिति है।

रणनीतकि बक्रिरी क्या है?

- कसिी कंपनी की रणनीतकि बक्रिरी के तहत कसिी रणनीतकि सहभागी को शेयरों के ब्लॉक का हस्तांतरण कयिा जाता है तथा प्रबंधन नयिंत्रण का हस्तांतरण भी कयिा जाता है। सामान्यतः रणनीतकि बक्रियिों से सरकार की शेयर होल्डगि क्षमता को 51 प्रतशित से कम कर दयिा जाता है।
- यह वशिष रूप से वनिविेश का मामला है जो कशियरों के हस्तांतरण के माध्यम से सरकार को न केवल बेहतर राजस्व उपलब्ध करवाता है बल्क कौशल सुधार के द्वारा कंपनी की वृद्ध दिर को प्रोत्साहति करने के लयि अनुभवी कॉरपोरेट्स को कंपनी का प्रबंधन नयिंत्रण सौंपता है।

रणनीतकि बक्रिरी क्यों?

कसिी रणनीतकि नविशक को कंपनी की इक्वटिी के शेयरों से प्राप्त होने वाली आय को आवश्यक अवसंरचनाओं के नरि्माण में अधकि लाभप्रद तरीके से पुनर्नियिोजति कयिा जा सकता है। यह सार्वजनकि क्षेत्र की कंपनयिों को प्रतस्पिर्द्धात्मक रूप से सक्षम बनाते समय सार्वजनकि ऋण में कमी करने में भी सहायता करेगा तथा ऋण-जीडीपी अनुपातको भी कम करेगा।

भारत में वनिविेश

- भारत में वनिविेश की शुरुआत सबसे पहले वर्ष 1991 में हुई जब सरकार ने कुछ चुनी हुई सार्वजनकि क्षेत्र की कंपनयिों का 20 प्रतशित हस्सिा बेचने का नरि्णय लयिा था। वर्ष 1993 में रंगराजन समतिि ने सार्वजनकि क्षेत्र के लयि आरक्षति सार्वजनकि क्षेत्र की इकाइयों में से 49 प्रतशित के वनिविेश तथा अन्य सभी सार्वजनकि क्षेत्र की इकाइयों के लयि 74 प्रतशित के वनिविेश का प्रस्ताव दयिा था। हालाँकयि सफिारशिें लागू नहीं हो सकीं।
- वर्ष 1996 में जी.वी.रामकृष्णा के नेतृत्व में एक गैर-सांवधिकि व सलाहकारी प्रकृत का वनिविेश आयोग स्थापति कयिा गया तथा वति्त मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1999 में एक बड़े कदम के रूप में वनिविेश वभिाग स्थापति कयिा गया। वर्ष 2004 में तत्कालीन सरकार ने एक ‘साझे न्यूनतम कार्यक्रम’ के साथ ही बीमार सार्वजनकि क्षेत्र की कंपनयिों को पुनर्जीवति करने व उन्हें वाणज्यिकि स्वायत्तता प्रदान करने की घोषणा की। इसके बाद वर्ष 2005 में राष्ट्रीय नविेश कोष स्थापति कयिा गया, जसिके माध्यम से वनिविेश की प्रक्रयिा आयोजति की जाती थी।
- वर्ष 2014 में नई वनिविेश नीत का सूत्रपात हुआ और वनिविेश के संबंध में सफिारशिी शक्तयिाँ नीतआियोग में अधकि़ृत की गईं।

नई वनिविेश नीत, 2014

इस नीत की महत्त्वपूर्ण वशिषताएँ

- केंद्रीय सार्वजनकि क्षेत्र के उद्यमों (CPSES) के सार्वजनकि स्वामत्वि को प्रोत्साहन देना। अधसिूचति CPSES में अल्पांश की बक्रिरी को जारी रखते हुए सरकार के बहुलांश हस्सिे को बरकरार रखना। चहि्नति CPSES में सरकारी हस्सिेदारी के प्रभावी हस्सिे (50 प्रतशित या अधकि) की बक्रिरी के साथ ही प्रबंधन नयिंत्रण के हस्तांतरण के द्वारा रणनीतकि वनिविेश।
- इस नीत का उद्देश्य CPSES में नविेश के कुशल प्रबंधन द्वारा नविेशकों, कर्मचारयिों, सरकार और कंपनी के लयि CPSES की कीमत उजागर करना, नरि्णय नरि्माण प्रक्रयिा की तर्कसम्मत व्याख्या करना तथा नविेशकों के भरोसे में सुधार करने के लयि उपयुक्त प्रबंधन रणनीतयिों को अंगीकार करना।
- इस नीत में नविेश और लोक परसिंपत्त प्रिबंधन वभिाग (DIPAM) को यह अधकिार प्रदान कयिा गया है क वह संबंधति प्रशासकीय मंत्रलयों से परामर्श के बाद सरकार के शेयरों की बक्रिरी के लयि CPSES को चहि्नति करे।
- रणनीतकि वनिविेश के लयि CPSES को चहि्नति करने, बक्रिरी के तरीके के बारे में सुझाव देने, बक्रिरी शेयरों का प्रतशित तय करने तथा CPSES के मूल्य नरि्धारण के तरीके को नश्चिति करने के लयि नीतआियोग को अधकि़ृत कयिा गया है।

आगे का रास्ता

- बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा के इस नए माहौल में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों को अपने अधिकारों की (कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत) हिफाजत करते हुए देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को मिलने वाले संरक्षण तथा किसी भी रणनीतिक सहयोगी को कंपनी चलाने के लिये मिलने वाली संभावित छूट के बीच एक समझौते की ज़रूरत है।
- रणनीतिक सहभागियों द्वारा परिसंपत्तियों को अलग करना (जैसे कि कंपनियों की परिसंपत्तियों का निपटान), उससे लाभ कमाना और अंततः संबंधित उद्योग का दोहन करने के पश्चात् उसे छोड़ देना सरकार के लिये चिंता का विषय है। इसलिये सरकार के पास ऐसी स्थितियों से निपटने के लिये कानून होना चाहिये।

यद्यपि सरकार ने इक्विटी में बिक्री के लिये CPSES को चिह्नित करने वाली एक व्यवस्थित मूल्यांकन प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है। अतः इसका पूरी पारदर्शिता के साथ सभी मामलों में पालन किया जाना चाहिये।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/strategic-sales-of-public-sector-companies